



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 266 राँची, सोमवार, 15 चैत्र, 1938 (श०)
4 अप्रैल, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

4 अप्रैल, 2016

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Contempt Petition No. 431/2013 in Civil Appeal No.7290/94 Swaminath Ray vrs. R.S. Sharma & Others एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में ।

संख्या- परि०वि० (निगम)-01/2016-480&सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127 दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 एवं अधिसूचना संख्या-54 दिनांक 14 जनवरी, 2004 द्वारा दिनांक-30 जून, 2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्तों एवं

प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या-7290/94 (सिविल अपील संख्या) में पारित आदेश दिनांक-12 अगस्त, 2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24 अगस्त, 2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि "In paragraph 9 of the report, it averred as under "9. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस संबंध में श्री तपेश कुमार सिंह, झारखण्ड सरकार के स्टैंडिंग कौंसिल के पत्रांक-36/2015 दिनांक-7 फरवरी, 2015 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि वैसे पथ परिवहन निगम के कर्मचारी जो समायोजन के क्रम में सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें दिनांक 24 अगस्त, 2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करना है।

इसी क्रम में दिनांक-24 अगस्त, 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association द्वारा अवमाननावाद सं0-203/2012, 229/2013, 359/2013, एवं 431/2013 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2011 के साथ सम्मिलित कर दिनांक-7 अप्रैल, 2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है- "It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind."

2- राज्य पथ परिवहन निगम के विभाजनोपरान्त झारखण्ड राज्य में दिनांक-24.08.2011 को 791 कर्मि कार्यरत थे। परिवहन विभाग के संकल्प गजट संख्या- 362 दिनांक 7 जून, 2013 यथा ***"उल्लेखित कर्मियों का समायोजन संकल्प निर्गत तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।"*** के आलोक में दिनांक 1 मार्च, 2013 को कार्यरत 609 कर्मियों में से 340 कर्मियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 से समायोजित किया गया। पुनः संकल्प गजट संख्या- 406 दिनांक- 28 अगस्त, 2014 के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या-104 दिनांक- 29 अगस्त, 2014 यथा ***"नियुक्ति (समायोजन) संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा।"*** के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या-105

दिनांक 1 सितम्बर, 2014 द्वारा कुल 203 कर्मियों का समायोजन किया गया। इस प्रकार कुल 543 कर्मियों की समायोजन राज्य सरकार की सेवा में किया जा चुका है। संकल्प गजट संख्या-94 दिनांक- 18 फरवरी 2015 द्वारा शेष 248 सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को दिनांक-24.08.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं श्री तपेश कुमार सिंह, स्टैंडिंग कौंसिल, झारखण्ड सरकार से प्राप्त मंतव्य तथा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2015, मद संख्या-07 में दिये गये स्वीकृति- "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूंकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय" के आलोक में दिनांक-24.08.2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित किया गया है।

3. इस प्रकार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों को संकल्प गजट संख्या-94 दिनांक-18 फरवरी, 2015, संकल्प गजट संख्या-362 दिनांक 7 जून, 2013, संकल्प गजट संख्या-406 दिनांक-28 अगस्त, 2014 विभिन्न तिथियों से समायोजित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय एवं दिनांक-03 मार्च, 2015 को मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प गजट संख्या-362 दिनांक 7 जून, 2013 एवं संकल्प गजट संख्या- 406 दिनांक- 28 अगस्त, 2014 के द्वारा समायोजित कर्मी भी दिनांक 24 अगस्त, 2011 से ही राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रतन कुमार,
सचिव,
परिवहन विभाग ।
